होर्मुज से निकले 30 भारतीय जहाज

जहाजों में कच्चा तेल, एलपीजी, एलएनजी और उर्वरक जैसे आयातित उत्पाद भारत लाए जा रहे हैं

नई दिल्ली, 26 जून ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने तथा युद्धविराम की दिशा में बढ़ते घटनाक्रम के बाद वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद अहम होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) में जहाजों की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य होने लगी है.

इसी बीच राहत की खबर यह है कि अब तक 30 भारतीय जहाज इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से सुरक्षित निकल चुके हैं. इन जहाजों में भारत के लिए कच्चा तेल, रसोई गैस (एलपीजी), तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और उर्वरक जैसे आवश्यक उत्पाद लाए जा रहे हैं. हालांकि, 20 से अधिक भारतीय जहाज अब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, हाल के दिनों में क्षेत्र में बढ़े सैन्य तनाव और सुरक्षा संबंधी जोखिमों के कारण कई जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य में प्रवेश करने या वहां से गुजरने से पहले इंतजार करना पड़ा था. स्थिति सामान्य होने के बाद अब जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है और भारतीय जहाज भी धीरे-धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया के देशों से आयात करता है. देश के कुल कच्चे तेल आयात का बड़ा भाग इसी समुद्री मार्ग से होकर आता है.

> होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में शामिल है. फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला यह संकरा समुद्री रास्ता वैश्विक तेल व्यापार की जीवनरेखा माना जाता है. दुनिया के समुद्री मार्ग से होने वाले कच्चे तेल के व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है. इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी तरह का सैन्य तनाव या अवरोध अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है.

निर्यात मई में रिकॉर्ड 12 .31 अरब डॉलर पर

नयी दिल्ली, 26 जून पश्चिम एशिया संकट और उससे उत्पन्न व्यापारिक व्यवधानों के बीच भारत से इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात इस साल मई में पहली बार 12 अरब डॉलर पर पहुंच गया.

पिछले साल मई में यह 9.89 अरब डॉलर था. इस प्रकार सालाना आधार पर इसमें 24.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी. सरकार द्वारा जारी त्वरित अनुमान के अनुसार, मई में देश के कुल माल निर्यात में इंजीनियरिंग उत्पादों का योगदान 27.2 प्रतिशत रहा. इंजीनियरिंग उत्पाद निर्यातकों के संगठन ईईपीसी इंडिया की शुक्रवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि रिकॉर्ड निर्यात मुख्य रूप से विद्युत मशीनरी एवं उपकरण, जहाज एवं नौकाएं, मोटर वाहन, लोहा-इस्पात तथा उनके उत्पादों के बेहतर प्रदर्शन के कारण संभव हुआ.

एक जुलाई से बदलेंगे कई वित्तीय नियम

यूपीआई से पीएफ निकासी की सुविधा शुरू होने की संभावना

क्रेडिट कार्ड पर लाउंज सुविधा और रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियम भी बदलेंगे

नई दिल्ली, 26 जून एक जुलाई 2026 से देश में कई महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका असर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा. कर्मचारी भविष्य निधिकी निकासी, पासपोर्ट शुल्क, क्रेडिट कार्ड सुविधाओं और केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते से जुड़े नियमों में बदलाव होने की संभावना है.

ऐसे में नौकरीपेशा लोगों, पेंशनभोगियों, यात्रियों और क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए इन नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी है, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी या अतिरिक्त खर्च का सामना न करना पड़े. सबसे बड़ा बदलाव कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ा हो सकता है. ईपीएफओ जुलाई में अपना नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ईपीएफओ 3.0 शुरू कर सकता है. इसके लागू होने पर खाताधारकों को यूपीआई के माध्यम से सीधे अपने पीएफ खाते से राशि निकालने की सुविधा मिल सकती है. वर्तमान व्यवस्था में पीएफ का पैसा मिलने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन नई प्रणाली लागू होने के बाद यह प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज और आसान हो सकती है.

> क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए भी नए नियम लागू होंगे. एचडीएफसी बैंक ने अपने रेगालिया गोल्ड और डाइनर्स क्लब प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया है. एक जुलाई से रेगालिया गोल्ड कार्डधारकों को घरेलू हवाई अड्डों पर मुफ्त लाउंज सुविधा का लाभ लेने के लिए पिछली तिमाही में कम से कम 60 हजार रुपये खर्च करने होंगे. निर्धारित खर्च पूरा नहीं होने पर मुफ्त लाउंज सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.

सिर्फ 55 महीना देकर 60 साल बाद 3,000 रुपए पेंशन पाएं

18 से 40 साल की उम्र वाले लोग आवेदन कर सकते हैं

मासिक आय 15,000 या उससे कम होनी चाहिए

नई दिल्ली, 26 जून देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोग जैसे मजदूर, किसान, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, दर्जी, ड्राइवर और रेहड़ी-पटरी विक्रेता अक्सर अपने बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं. इन लोगों के पास न तो कोई पेंशन होती है और न ही रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का कोई साधन.

इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है. यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने निश्चित पेंशन देना है. इस योजना की खासियत यह है कि इसमें बहुत कम पैसे जमा करने होते हैं. अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है, तो उसे सिर्फ 55 प्रति माह जमा करने होते हैं. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, योगदान राशि बढ़ती जाती है और 40 साल की उम्र तक यह 200 प्रति माह तक पहुंच जाती है.

एसआईपी उछाल पर जेपी मॉर्गन भरोसेमंद

मुंबई, 26 जून भारत में तेजी से बढ़ते सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को पूंजी बाजार की सबसे बड़ी मजबूती बताते हुए विदेशी ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन ने एसेट मैनेजमेंट और कैपिटल मार्केट्स से जुड़ी कई कंपनियों पर भरोसा जताया है. ब्रोकरेज का मानना है कि खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी, एसआईपी के जरिए लगातार आ रहा निवेश और अनुकूल नियामकीय माहौल आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की वृद्धि को नई गति देंगे. इसी आधार पर उसने एंजेल वन, सीएएमएस , प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट और एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपनी पसंदीदा निवेश सूची में शामिल करते हुए इन पर 'ओवरवेट' रेटिंग दी है.

छोटे शहरों से आसान विदेशी उड़ान

सरकार ने 'हब एंड स्पोक' मॉडल लागू किया, जिससे शहरों से विदेश यात्रा आसान हो गई

नई दिल्ली, 26 जून देश के छोटे शहरों से विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 'हब एंड स्पोक मॉडल' की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत अब टियर-2 और टियर-3 शहरों से यात्रा करने वाले यात्रियों को दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट पर दोबारा इमिग्रेशन या बैगेज चेक-इन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा.

इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद यात्री अपने होम एयरपोर्ट से ही अंतरराष्ट्रीय यात्रा की सभी औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे. यानी एक ही बार में चेक-इन, सुरक्षा जांच और इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आगे की

अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए उन्हें किसी बड़े हब एयरपोर्ट पर दोबारा प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा. इससे यात्रियों का समय बचेगा और यात्रा पहले से अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाएगी.

> सरकारी जानकारी के अनुसार, देश में वर्तमान में 36 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें से 6 प्रमुख हब एयरपोर्ट के रूप में काम करते हैं. अब तक छोटे शहरों से अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों को दिल्ली, मुंबई या अन्य बड़े शहरों में ट्रांजिट और दोबारा चेक-इन की परेशानी झेलनी पड़ती थी. लेकिन नए मॉडल के तहत यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी. इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है.

जीएसटी भुगतान से घटी बैंकिंग नकदी, आरबीआई सक्रिय

1.41 लाख करोड़ रुपये बैंकिंग प्रणाली में डालकर नकदी की कमी दूर करने का प्रयास किया

मुंबई, 26 जून बैंकिंग प्रणाली में नकदी की कमी को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सात-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी के जरिए 1.41 लाख करोड़ रुपये से अधिक की नकदी उपलब्ध कराई है.

केंद्रीय बैंक ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब जीएसटी और अग्रिम कर के भुगतान के कारण बैंकिंग प्रणाली से बड़ी मात्रा में धन निकलने से नकदी पर दबाव बढ़ गया है. आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, सात-दिवसीय वीआरआर नीलामी के माध्यम से 1,41,171 करोड़ रुपये 5.26 प्रतिशत की कट-ऑफ और भारित औसत दर पर उपलब्ध कराए गए. इससे पहले 21 जून को बैंकिंग प्रणाली में 30,685.11 करोड़ रुपये की अधिशेष नकदी थी, जो 22 जून तक घटकर 19,971.89 करोड़ रुपये के घाटे में बदल गई. नकदी की इस कमी ने अल्पकालिक मुद्रा बाजार की ब्याज दरों पर दबाव बढ़ा दिया.

जीएसटी और अग्रिम कर भुगतान के कारण बड़ी मात्रा में धन बैंकिंग प्रणाली से निकलकर सरकार के खाते में चला गया, जिससे बैंकों के पास उपलब्ध नकदी कम हो गई. इसी वजह से बैंकों की अल्पकालिक फंडिंग लागत बढ़ने लगी और ओवरनाइट कॉल मनी दर 5.43 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो आरबीआई की रेपो दर से 0.18 प्रतिशत अधिक है. इसी तरह ट्राई-पार्टी रेपो की दरें भी नीतिगत रेपो दर से 0.05 से 0.07 प्रतिशत ऊपर कारोबार कर रही थीं. नकदी की स्थिति को सामान्य बनाए रखने और अल्पकालिक ब्याज दरों को रेपो दर के करीब रखने के उद्देश्य से आरबीआई लगातार वीआरआर नीलामियों के जरिए बैंकिंग प्रणाली में अस्थायी नकदी डाल रहा है. पिछले कुछ दिनों के दौरान केंद्रीय बैंक विभिन्न अवधियों की वीआरआर नीलामियों के माध्यम से करीब 2.43 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध करा चुका है.

> कर भुगतान से उत्पन्न नकदी दबाव अस्थायी होता है और सरकार के खर्च बढ़ने के साथ यह धन दोबारा बैंकिंग प्रणाली में लौट आता है. तब तक आरबीआई जरूरत के अनुसार वीआरआर जैसे साधनों का उपयोग कर बाजार में पर्याप्त नकदी बनाए रखता है, ताकि बैंकों के लिए धन की उपलब्धता बनी रहे और अल्पकालिक ब्याज दरों में अनावश्यक उतार-चढ़ाव न आए. इससे वित्तीय बाजार में स्थिरता बनाए रखने और मौद्रिक नीति के प्रभावी संचालन में भी मदद मिलती है.

टाटा का अपने यात्री वाहन डीलरों को आसान ऋण

उपलब्ध कराने के लिए यूको बैंक से करार

इन्वेंट्री की बिना पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा

मुंबई, 26 जून टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (टीएमपीवी) और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (टीपीईएम) ने अपने अधिकृत डीलरों को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए यूको बैंक के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है.

टीएमपीवी और यूको बैंक ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि इससे डीलरों की रोजमर्रा की पूंजी आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकेगा. इस साझेदारी के तहत डीलरों को उनकी जरूरतों के अनुरूप उनके पास मौजूद इन्वेंट्री की बिना पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा. दोनों कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये.

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी धीमन गुप्ता ने इस साझेदारी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से कंपनी के अधिकृत डीलर साझेदारों को टाटा की पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाले और इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी. डीलर नेटवर्क कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह सहयोग डीलरों को अपनी इन्वेंट्री का बेहतर प्रबंधन करने में सक्षम बनायेगा.

वाराणसी से ओमान बिस्कुट निर्यात शुरू

वाराणसी, 26 जून देश के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ओमान के लिए बिस्कुट की पहली निर्यात खेप की सुविधा प्रदान की है. यह कदम भारत और ओमान के बीच हाल ही में हुए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद एक अहम शुरुआत माना जा रहा है.

इस निर्यात के तहत करीब 40 मीट्रिक टन बिस्कुट ओमान भेजे गए हैं.

आईटीआर भरने वालों के लिए अहम चेतावनी

नई दिल्ली, 26 जून अगर आपने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर दिया है, तो 30 जून आपके लिए एक महत्वपूर्ण तारीख है.

इस दिन तक आयकर विभाग कुछ रिटर्न को जांच के लिए चुन सकता है और आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के तहत स्क्रूटनी नोटिस जारी कर सकता है. हालांकि, ऐसा नोटिस मिलने का अर्थ यह नहीं है कि आपने कोई गलती की है या कर चोरी की है. कई मामलों में विभाग केवल रिटर्न में दी गई जानकारी का सत्यापन करता है.

स्क्रूटनी नोटिस वह प्रक्रिया है, जिसके तहत आयकर विभाग यह जांच करता है कि करदाता द्वारा घोषित आय, छूट, कटौतियां और निवेश संबंधी जानकारी उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं. इसके लिए विभाग फॉर्म 26एएस, वार्षिक सूचना विवरण टैक्सपेयर सूचना सारांश बैंकिंग रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय आंकड़ों का मिलान करता है.

समाचार विशेष

मिशन पंडित जी : मायावती ने भी छेड़ा अभियान

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करने में जुटे हुए हैं. पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन कराया. वहीं कुछ माह पहले सुभासपा अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन कराया था.

अन्य पार्टियां भी ब्राह्मणों को अपने साथ लाने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटी हुई हैं. बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती लगातार ब्राह्मणों के लिए आवाज उठा रही हैं और विपक्षी दलों को आईना दिखा रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व ब्राह्मणों को दिया गया था. वह बार-बार इस बात को याद भी दिलाती हैं.

बसपा सुप्रीमो ने सोमवार को एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए विरोधी दलों को याद दिलाया कि कैसे बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों के साथ खड़ी है. बसपा अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्ट पर पोस्ट किया है कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र जब से अपर कास्ट समाज और उसमें से ख़ासकर ब्राह्मण समाज को, उनके बीएसपी में जुड़ने को ध्यान में रखकर, पार्टी का उम्मीदवार बनाना शुरू कर दिया है, तब से सभी विरोधी पार्टियों में व ख़ासकर समाजवादी पार्टी में उनकी नींद उड़ा देने वाली बेचैनी देखने को मिल रही है.

> **बसपा संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति नहीं करती**
>
> इसके साथ ही अपरकास्ट में से क्षत्रिय, वैश्य व अन्य समाज के लोगों को भी उनकी बसपा से जुड़ने की तैयारी यानी जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर चुनाव में उम्मीदवार भी ज़रूर बनाया जायेगा, जिसकी तैयारी हर स्तर पर लगातार जारी है. बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कुछ लोगों को लॉलीपाप थमाने की संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति नहीं करती है, बल्कि पूरे समाज के हित व कल्याण की चिन्ता करना अपना संवैधानिक कर्तव्य समझती है और इसीलिए बीएसपी की नीति व कार्यक्रम जनहित व जनकल्याण और अपराध नियंत्रण व क़ानून व्यवस्था के मामले में भी देश व जनहित में बेहतरीन होते हैं.

2029 से पहले बीजेपी का बड़ा मास्टरप्लान?

महिला आरक्षण और परिसीमन से बदलेंगे चुनावी समीकरण

नई दिल्ली. बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का पूरा अहसास है कि 2029 की चुनावी डगर, 2024 के मुकाबले कहीं अधिक कठिन हो सकती है. इसलिए, पार्टी ने दो प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है—महिला आरक्षण और परिसीमन. क्या आने वाले समय में इन मुद्दों से राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? हर कोई इसी का इंतजार कर रहा है.

महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में काफी ध्यान दिया है. यह न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जरूरी है, बल्कि पार्टी को

भी वोट बैंक में बढ़त दिला सकता है. यदि यह बिल संसद में पास होता है, तो बीजेपी को मुद्दा आधारित राजनीति में फायदा होने की उम्मीद है.

परिसीमन की प्रक्रिया का असर जम्मू-कश्मीर और असम में पहले से देखने को मिला है. जम्मू में 6 नई विधानसभा सीटें जोड़ी गईं, जिससे बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिला. अब बीजेपी की नजर उन राज्यों पर है जहां 2024 में उसे सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा था—उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल.

इन तीन राज्यों में लोकसभा की कुल 170 सीटें हैं. 2024 में एनडीए को यहां सिर्फ 65 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, जबकि विपक्ष यानी 'इंडिया' गठबंधन ने 105 सीटें जीती थीं. ऐसे में, बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव लाना ही होगा, क्योंकि भविष्य के परिसीमन का सबसे बड़ा असर इन्हीं राज्यों पर पड़ सकता है.

> **राजनीतिक हलचल का असर**
>
> महाराष्ट्र में शिवसेना की अंतर्विरोधी स्थिति और बंगाल में टीएमसी की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है. राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि तमिलनाडु की डीएमके और एम.के. स्टालिन का रुख भी महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर जब बात संवैधानिक बदलाव की हो. बीजेपी ने इन सारी अटकलों को महज विपक्ष का आंतरिक मामला बताया है. लेकिन यह स्पष्ट है कि यह पूरी प्रक्रिया केवल संख्या बल जुटाने तक सीमित नहीं रह सकती.

पंजाब में इस बार बहुकोणीय संघर्ष

चंडीगढ़. पंजाब में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पांच से ज्यादा बड़ी पार्टियां पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगी. पहले दो पार्टियों के बीच चुनाव होता था. कांग्रेस और अकाली दल के बीच मुकाबला होता था, जिसमें भाजपा और अकाली दल मिल कर लड़ते थे.

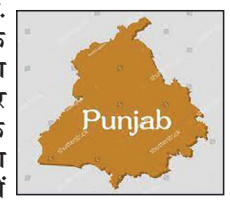

इसके बाद पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई. इस तरह त्रिकोणात्मक मुकाबले शुरू हुए. पिछले चुनाव से पहले भाजपा और अकाली दल का तालमेल टूट गया तो भाजपा अकेले चुनाव लड़ी. इस तरह पंजाब में चारकोणीय मुकाबला हुआ. हालांकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ही था. अकाली दल को सिर्फ तीन ही सीटें मिलीं लेकिन उसको 18 फीसदी से ज्यादा वोट मिले. कांग्रेस ने 18 सीटें जीतीं और उसे 23 फीसदी के करीब वोट मिले. भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को सिर्फ दो सीटें मिलीं लेकिन वोट आठ फीसदी के करीब मिले.

इस बार भी ये चारों पार्टियां या गठबंधन मुकाबला करेंगी. लेकिन इस बार इन चार पार्टियों के अलावा भी नई पार्टियां मैदान में हैं.

विशेष — मुस्लिम वोट बैंक में नई जमीन तलाशने की तैयारी

चुनावों से पहले बीजेपी का मिशन पसमांदा

जयपुर. राजस्थान की राजनीति में आगामी पंचायत, निकाय और विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के भीतर नई राजनीतिक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश में 'मिशन पसमांदा' की शुरुआत करने जा रहा है.

ये अभियान कांग्रेस के परंपरागत पसमांदा मुस्लिम वोट पर सेंधमारी के तौर पर है. इस अभियान का केंद्र मुस्लिम समाज की पिछड़ी और सामाजिक रूप से वंचित उपजातियों तक पहुंच बनाना होगा. भजनलाल सरकार की नीतियों को अल्पसंख्यक मोर्चा के जरिए पसमांदा मुस्लिमों के बीच प्रचारित किया जाएगा. जुलाई से इस प्रस्तावित अभियान के जरिये 25 लाख मुसलमान बहुल 40 विधानसभा सीटों पर सघन जनसंपर्क करेगी.

बीजेपी की रणनीति केवल पारंपरिक चुनावी समीकरणों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी के नए विमर्श को सामने लाने की कोशिश भी मानी जा रही है. पार्टी संगठन का मानना है कि लंबे समय से मुस्लिम राजनीति सीमित नेतृत्व के इर्द-गिर्द केंद्रित रही है, जबकि पिछड़े और पसमांदा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पीछे रहे हैं. इसी सोच के तहत भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मेव, कायमखानी, कुरैशी, मंसूरी, मिरासी, देशवाली, बोहरा, सिंधी मुसलमान, पठान, गद्दी मुसलमान सहित विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संपर्क अभियान चलाएगा. अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने बताया कि इन समुदायों का प्रभाव अलवर, भरतपुर, नागौर, टोंक, जयपुर, कोटा, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, जैसलमेर और अजमेर सहित कई जिलों में माना जाता है.

भरोसा दिलाना बड़ी चुनौती- राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा के कहते हैं कि भाजपा का 'मिशन पसमांदा' केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि सामाजिक पुनर्संवाद की कोशिश के रूप में सामने आ रहा है. लंबे समय से मुस्लिम राजनीति पर सीमित नेतृत्व के प्रभाव की चर्चा होती रही है, जबकि पसमांदा और पिछड़े मुस्लिम वर्ग प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी के सवाल उठाते रहे हैं. भाजपा इसी सामाजिक अंतराल को अवसर में बदलने का प्रयास कर रही है.

> **बूथ स्तर की पकड़ मजबूत**
>
> हमीद खान मेवाती ने बताया कि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव बूथ स्तर की सामाजिक पकड़ को मजबूत करने का बड़ा माध्यम होते हैं. ऐसे में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा स्थानीय नेतृत्व तैयार करने और भविष्य के उम्मीदवारों की जमीन बनाने की दिशा में भी काम कर सकता है. बीजेपी के इतिहास पर नजर डालें तो पार्टी और उसके पूर्ववर्ती दौर में मुस्लिम प्रतिनिधित्व पूरी तरह अनुपस्थित नहीं रहा. 1977 के चुनावों में जनता पार्टी दौर में मुस्लिम विधायक चुने गए थे. भाजपा गठन के बाद भी समय-समय पर मुस्लिम नेताओं को टिकट और राजनीतिक जिम्मेदारियां दी गईं. युनुस खान, हबीबुर्रहमान, अब्दुल सगीर जैसे नाम विधानसभा राजनीति में सक्रिय रहे.